मुख्यमंत्री व शिवराज सिंह ने मेड़ता में किसानों को 1200 करोड़ रु. हस्तांतरित किये

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2000 करोड़ रु. के स्वीकृति पत्र सौंपे

नागौर/जयपुर, 23 दिसम्बर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि किसानों का फसल उत्पादन बढ़े तथा उनकी लागत में कमी आए।

- किसान सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट तथा पैस्टिसाइड एक्ट लाने वाली है, जिससे नकली पैस्टिसाइड व महंगे बीज देने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने मुख्यमंत्री को हल भेंट किया।

चौहान मंगलवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत दो वर्षों में राजस्थान में विकास का नया अध्याय रचा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर 9 हजार रुपये किया है।

चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट एवं पैस्टिसाइड एक्ट लाने वाली है जिससे नकली पैस्टिसाइड एवं महंगे बीज देने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है तथा शीघ्र ही वंचित गरीबों को मकान देने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है तब अन्नदाता अपने खेतों में जागते हैं। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या आंधी तूफान, किसानों का काम कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक किसान रहे हैं इसलिए वे खेती में आ रही समस्याओं को भली-भांति समझते हैं।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली जैसे अनेक किसान हित में निर्णय लिए हैं। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले बैच में 3 हजार 200 किलोमीटर से अधिक की 1,216 सड़कों एवं एक पुल के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये के कार्यों का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण योजनाओं के तहत 35 हजार 800 किसानों को 187.60 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की। साथ ही, 5 लाख कृषकों को कृषि आदान अनुदान के रूप में 617 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि भी खातों में भेजी गई।

उन्होंने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को 150 करोड़ रुपये की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 18 हजार 500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की।

देश भर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है, उनका कहना है कि सरकार अरावली को खनन माफिया और भूमाफियाओं को बेचने की कोशिश कर रही है, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाने का बड़ा जोखिम पैदा करेगा।

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस डर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि जब तक एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार और अनुमोदित नहीं की जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली में से केवल 0.19 प्रतिशत ही खनन के योग्य है। अवैध खनन के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए मंत्री ने कहा कि नया नियम ऐसे कार्यों पर नियंत्रण लगाने और "कानूनी रूप से सतत खनन" की अनुमति देने के उद्देश्य से है। हालांकि, उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अवैध खनन गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जाएगी। एक्टिविस्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अरावली की नई परिभाषा के कारण स्थिति ऐसी बन जाएगी कि 90 प्रतिशत पहाड़ियां अब अरावली के रूप में नहीं मानी जाएंगी। मंत्री ने यह स्पष्ट करने में विफलता जताई कि कितनी पहाड़ियां संरक्षित की जाएंगी और कितनी प्रभावित होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2010 में फॉरेस्ट सर्वे इंडिया भारत की एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि अरावली की लगभग 12,000 पहाड़ियों में से केवल 8 प्रतिशत पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं।

पूरे पुराने बंगाल प्रांत में ...

- बांग्लादेश में इस्लामिक जूनून, जो पाकिस्तानी व बांग्लादेश के जमाती धर्मालम्बियों के आपसी सहयोग से चरम पर पहुंच गया है, का निशाना भी उस देश में रहने वाला आम हिन्दू ही है।
- यह माना जा रहा है कि यह हिंसा का दौर, प.बंगाल के चुनाव तक यूँ ही बढ़ता जायेगा, पर फिर क्या इस नाग को दोबारा पिटारी में बंद किया जा सकेगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोषियों को सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं, पुलिस थाने आम तौर पर मुस्लिम अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर देते हैं।

इसके बावजूद, ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब उनके लिए पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही है। एक मुस्लिम, जो मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ को कम कर रहा है वह उन्हीं के जैसा एक व्यक्ति है और उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। हुमायूं कबीर नामक एक दलबदलू नेता, जो पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता रहा है, ने अब अपनी नई पार्टी बना ली है और अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे रहा है। कबीर ने पहले मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं को "काटने" और लाशों को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की धमकी दी थी। उसने यह दावा किया था कि मुर्शिदाबाद की आबादी में 80 प्रतिशत मुस्लिम हैं।

पश्चिम बंगाल से भी कहीं ज्यादा भयावह हालात बंगाल के दूसरे हिस्से, यानी बांग्लादेश में हैं, जहां इतनी हिंसा फैल चुकी है जो हाल के वर्षों में शायद ही कभी देखी गई है। कट्टर इस्लामी भीड़ देश में तबाही मचा रही है और हिंदुओं पर हमले बेहिसाब बढ़ गए हैं।

बांग्लादेश में एक हिंदू गारमेंट मजदूर की नृशंस हत्या ने भारत में गंभीर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस घटना का लगभग कोई असर नहीं दिखा और शायद ही कोई इसकी परवाह कर रहा है। यह ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के आदेशों के आगे पूरी तरह झुके होने की स्थिति को दर्शाता है।

एक व्यक्ति की अमानवीय हत्या को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में खुशी-खुशी प्रसारित किया गया, जिसमें दर्जनों हमलावरों को मृत शरीर को रौंदते हुए और बाद में उसके क्षतविक्षत शरीर को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया। यह सब बांग्लादेशी समाज में बढ़ती बर्बरता को उजागर करता है।

दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रमुख विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर सरकार की चुप्पी की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार के मौन रहने पर हमला बोला है, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इतनी बर्बरता के सामने केंद्र के चुप रहने की निंदा की है।

पिछले सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश अराजकता की स्थिति में है, जब बड़े जनविद्रोह के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थीं। तब से एक अंतरिम सरकार सत्ता में है, जिसके दौरान अपराध और हिंसा का बोलबाला रहा है।

यह सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जमातियों की मदद से कराया था और इसके बाद से इस्लामी हिंसा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है।

वर्तमान हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एक राजनीतिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कई अन्य लोगों पर भी हमले हुए और अब पूरे देश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद से देश में थोड़ी भी व्यवस्था लाने में पूरी तरह नाकाम रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑपरेटर कई कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रित कर रहे हैं।

दुष्कर्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील रचना मान ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए हैं।

बांग्लादेश उच्चायोग पर भारतीयों का गुस्सा फूटा

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में कहा, "बांग्लादेश इस तरह की पूर्व-नियोजित हिंसा या राजनयिक प्रतिष्ठानों को डराने-धमकाने की घटनाओं की निंदा करता है, जो न केवल राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि आपसी सम्मान और शांति व सहिष्णुता के मूल्यों को भी कमजोर करती हैं।"

मंत्रालय ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इससे राजनयिक कर्मियों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा है और भारत से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

बयान में कहा गया, "बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह इन घटनाओं की गहन जांच कराए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और भारत में बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।"

इन घटनाओं में 22 दिसंबर 2025 को सिलीगुड़ी स्थित बांग्लादेश वीज़ा केंद्र में तोड़फोड़ और 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुआ प्रदर्शन शामिल है। भारत ने अपर्याप्त सुरक्षा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नई दिल्ली में हुआ प्रदर्शन थोड़े समय का था और इससे कोई खतरा नहीं पैदा हुआ।

अंकिता भंडारी मर्डर, एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रहे हैं कि गौतम ने ऋषिकेश के पास एक रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि उनके पास हत्या से जुड़े अतिरिक्त साक्ष्य हैं, जो उनके आरोपों की पुष्टि करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में एक रिज़ॉर्ट में हुई थी, जो कथित तौर पर विनोद आर्य, जो उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, के बेटे पुलकित आर्य और कार्यकर्ताओं के पास था। उस समय विनोद आर्य माटी आयोग के अध्यक्ष थे, तथा उनका स्तर मंत्री का था। कुछ महीने पहले हत्या के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला जब पहली बार सामने आया था, तब उत्तराखंड में व्यापक जन आक्रोश फैला था और विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन नए वीडियो के सामने आने से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में, उत्तराखंड कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा नियंत्रित केंद्र और राज्य सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

पार्टी ने धमकी दी है ऐसा नहीं हुआ तो गढ़वाल मंडल के प्रमुख कार्यालय में धरना और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने इस "भयंकर और नृशंस हत्या" की सीबीआई जांच की मांगों को नज़रअंदाज़ किया है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, गोदियाल ने कहा, कि भाजपा के प्रभावशाली लोग इस मामले में संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

गोदियाल के अनुसार, केंद्रीय जांच "जानबूझकर रोकी गई" क्योंकि यह रिसॉर्ट कथित तौर पर शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो "अवैध और अमानवीय गतिविधियों" में शामिल थे। उन्होंने इस मामले में शामिल सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई गैर-भाजपा राजनीतिक दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है जो इस युवा लड़की के यौन शोषण और हत्या में कथित रूप से शामिल हैं। वायरल वीडियो ने यह सुनिश्चित किया है कि अंकिता भंडारी मामला फिर से राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है, और सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस पर निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600